बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 179 ● नई दिल्ली ● बुधवार 16 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

पूरी तरह से सर्कस चला रहे हैं...शी जिनपिंग से मुलाक़ात को लेकर राहुल गांधी ने जयशंकर पर कसा तंज

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत-चीन संबंधों के बारे में =जानकारी= देने के लिए निशाना साधा और कहा कि वह देश की विदेश नीति को नष्ट करने के उद्देश्य से एक पूरी तरह से सर्कस चला रहे हैं। विपक्ष के नेता की यह टिप्पणी जयशंकर द्वारा मंगलवार को शी जिनपिंग से मुलाकात और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराने के बाद आई है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री आएंगे और मोदी को चीन-भारत संबंधों में हालिया घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे।

केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा- चार-चार इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से विफल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार को दो स्कूलों को धमकी मिलने के बाद मंगलवार को फिर सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को ऐसी ही धमकी मिली है। इन लगातार मिल रही धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के अधीन आती है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इन धमकियों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की चार-चार इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली में चार इंजन वाली बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और मंगलवार को एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली है, जिससे बच्चे डरे हुए हैं और अभिभावक बेहद चिंतित हैं। आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा

में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस स्थिति को बेहद डरावना और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार स्कूलों और कॉलेजों को बम की धमकियाँ मिलना सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। आतिशी ने सवाल उठाया, क्या इन बच्चों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है? कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर देश की राजधानी में स्कूल भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या सुरक्षित है? उन्होंने बताया कि बच्चे डर के साए में जी रहे हैं, और माता-पिता हर सुबह डर के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आप नेताओं ने याद दिलाया कि सोमवार को भी दिल्ली के दो बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पहले चाणक्यपुरी स्थित नेवी स्कूल को धमकी मिली थी, जिसके बाद द्वारका सेक्टर-16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को ऐसी धमकियां मिली हैं। कुछ महीने पहले भी इसी तरह की धमकियों का सिलसिला देखा गया था। उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई थी, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने तब भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आप ने पूछा कि अखिर दिल्ली में बीजेपी के चारों इंजन क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के बच्चे भी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं?

कालिंदी कुंज से नोएडा के बीच भारी जाम, दो घंटे से फंसे हैं लोग; कांवड़ यात्रा के चलते एक लाइन बंद

नई दिल्ली। दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर भारी जाम लग गया है। कालिंदी कुंज और नोएडा रोड के बीच गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। लोग दो घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस मार्ग पर कांवड़ के चलते एक सड़क बंद की गई है। इस वजह से यहां जाम की स्थिति बन गई है। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि यह व्यवस्था 13 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के नोएडा, कालिंदी कुंज और आगरा कैनाल रोड होते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान की ओर जाने की उम्मीद है। सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और यातायात को भीड़भाड़ से बचने के लिए 13 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक विशेष यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आगरा कैनाल रोड (कालिंदी कुंज से बदरपुर की ओर) का आधा कैरिजवे बंद। कालिंदी कुंज से नोएडा रोड का आधा कैरिजवे भी बंद। इस वजह से इन रास्तों पर भारी यातायात भीड़भाड़ की आशंका है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे कालिंदी कुंज के बजाय डीएनडी फ्लाईवे या आश्रम मार्ग से होकर जाएं। फरीदाबाद से नोएडा जाने वाले यात्री बदरपुर से आश्रम और डीएनडी होते हुए मथुरा रोड जाएं। क्योंकि कालिंदी कुंज-नोएडा कैरिजवे आंशिक रूप से बंद है। आपातकालीन सेवा वाहनों (दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग, आदि) को आपातकालीन ड्यूटी के दौरान प्रतिबंधित सड़कों पर जाने की अनुमति है, लेकिन परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए कालिंदी कुंज और आगरा नहर रोड से बचने की सलाह दी जाती है।

अरविंद केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन की सेहत का जाना हाल, सीएम हेमंत से की मुलाकात

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का हाल जाना। साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीएम शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल जाकर झारखंड के मुख्यमंत्री और मित्र हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके पिता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हालचाल जाना। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। वे दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सकों के अनुसार, ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके शरीर के बाईं

ओर पैरालिसिस हो गया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। आईसीयू में केवल सीमित लोगों को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अस्पताल में मौजूद हैं। शिबू सोरेन की हालत जानने के लिए झारखंड से कई मंत्री और कांग्रेस नेताओं ने भी दिल्ली पहुंचकर हालचाल लिया है, लेकिन सुरक्षा एवं चिकित्सकीय दिशा-निर्देशों के चलते सभी को मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा रही। बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता और कार्यकर्ता शीघ्र उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। रघुवर दास ने भी हेमंत सोरेन को फोन कर उनके पिता शिबू सोरेन की जानकारी ली है। शिबू सोरेन के बीमार होने के बाद से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, विधायक बसंत सोरेन लगातार दिल्ली में ही डेरा डाले हुए है।

साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीएम शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल जाकर झारखंड के मुख्यमंत्री और मित्र हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके पिता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हालचाल जाना।

कांवड़ यात्रा पथ पर दुकानों में अनिवार्य क्यूआर कोड मामले में अदालत सख्त, यूपी से 22 तक मांगा जवाब

नई दिल्ली । कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान उजागर करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 जून को यूपी सरकार द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए, शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा ने कहा कि नए निर्देश के तहत कांवड़ मार्ग पर बने सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इससे दुकान मालिकों के नाम और पहचान का पता चले। इससे दोबारा वही भेदभाव किया जा रहा है, जिसे पहले इस अदालत ने रोका था। याचिका में कहा गया कि राय सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों को कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने के लिए कहा गया है, दुकान, ढाबा और रेस्तरां मालिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। श्रावण मास के दौरान शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार से परहेज करते हैं। कई लोग तो प्याज और लहसुन वाला भोजन भी नहीं खाते।

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में समय रैना समेत पांच इंफ्लुएंसर पेश, दो हफ्ते का दिया समय

नई दिल्ली। दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने के मामले में समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने अगली सुनवाई में भी उनको अदालत में पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शारीरिक कारण से सोनाली ठक्कर को पेशी से छूट दे दी और उन्हें वर्चुअली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को दो हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा और जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी को सुनवाई में शामिल होने को कहा है। साथ ही सोशल मीडिया दिशा-निर्देश तैयार करने में भी मदद देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिशा-निर्देश तैयार करते समय अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की आजादी के अधिकार और कर्तव्य का भी संतुलन रखा जाए। अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति को बोलने की आजादी का अधिकार दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला; विक्रमजीत सिंह बने एसीबी के नए चीफ

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के 12 आईपीएस के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इन्हें एक यूनिट व जिले से हटाकर दूसरे यूनिट और जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब पौने तीन साल से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में तैनात रहे संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा की दिल्ली पुलिस में वापसी हो गई। एसीबी में आने से पहले उनकी तैनाती केंद्र शासित प्रदेश में थी। सुरक्षा यूनिट में तैनात संयुक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह को एसीबी का नया चीफ बनाया गया है। इससे पहले विक्रमजीत सिंह पूर्वी रेंज और नई दिल्ली रेंज में संयुक्त आयुक्त भी रहे। बाहर की पोस्टिंग काटकर लंबे समय बाद दिल्ली पुलिस में लौटे विशेष आयुक्त राजेश खुराना को दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले करीब दो माह से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में तैनात विशेष आयुक्त नीरज कुमार को फाइनेंस डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके पास विजिलेंस की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। फाइनेंस डिवीजन में तैनात विशेष आयुक्त गरिमा भटनागर को आर्थिक अपराध में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस अकादमी के डायरेक्टर संयुक्त आयुक्त धीरज कुमार को आर्म्ड फोर्स की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आर्म्ड फोर्स में संयुक्त आयुक्त एमएन तिवारी को सुरक्षा यूनिट भेज दिया गया। मधुर वर्मा को मध्य रेंज का संयुक्त आयुक्त बनाया गया है। पीसीआर में तैनात संयुक्त आयुक्त एवी देश पांडे को पीसीआर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उन्हें लाइसेंसिंग की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। लाइसेंसिंग में तैनात नूपुर प्रसाद को आर्थिक अपराध शाखा में भेज दिया गया। करीब तीन माह पहले ही उन्हें लाइसेंसिंग में लगाया गया था। सुरक्षा यूनिट में तैनात एडिशनल डीसीपी जगदेव सिंह को पूर्वी जिले में भेज दिया गया। पूर्वी जिले में तैनात एडिशनल डीसीपी सुनील को उत्तर-पश्चिम जिला और एसीपी मॉडल टाउन अभिषेक गुप्ता को प्रोन्नत कर एडिशनल डीसीपी सुरक्षा यूनिट में भेजा गया है।

पीएम मोदी पर बनाए कार्टून को सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ बताया, कार्टूनिस्ट को फटकारा, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को मंगलवार को संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सूर्यांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष अदालत कथित अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट से नाराज़ थी और उसने कहा लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं। हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई को पारित उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। प्रधानमंत्री और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून ऑनलाइन साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को उचतम न्यायालय का संरक्षण मिला। सोशल मीडिया पोस्ट आपत्तिजनक, सभी तरह के दंडनीय प्रावधान लागू हो सकते हैं। लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा। क्कौल और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जोशी ने आरोप लगाया कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालवीय की ओर से कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो शिकायतकर्ता अदालत आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया से हटाना चाहती हैं वो हटाएं।

डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को फिर से ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार (15 जुलाई) को द्वारका इलाके में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज परिसर को खाली करा लिया गया है। जांच में अभी तक पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बम की यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, सोमवार को एक के बाद दो

बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पहले सुबह सवा आठ बजे चाणक्यपुरी स्थित नेवी स्कूल फिर 8.25 बजे द्वारका सेक्टर-16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोनों मामलों की जांच के लिए स्पेशल सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से ईमेल भेजने वाले के बारे में पता लगा रही है। पिछले साल मई में दिल्ली के विभिन्न संस्थानों व स्कूलों को इसी तरह मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। पहली बार दिल्ली-एनसीआर के 200 से अधिक स्कूलों को उनके आधिकारिक ईमेल पर मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद कई अस्पतालों, कॉलेजों और दिल्ली हवाई अड्डे को भी इसी तरह के मेल भेजे गए थे। इस साल जनवरी में भी कई स्कूलों ने बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस को जांच में पता चला था कि यादातर ईमेल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल करके भेजे गए थे। वीपीएन का पूरा बिजनेस माडल इस सिद्धांत पर काम करता है कि सर्वर लोकेशन या विवरण का खुलासा नहीं करेगा। जिससे मेल भेजने वाले के बारे में दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल अब तक पता नहीं लगा पाई है। जून में मुंबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली थी, जब एयरलाइन के एक क्रू मेंबर को एक मुड़ा हुआ कागज मिला, जिसपर लिखा था कि एयर इंडिया 2948 में बम है। सीआईएसएफ द्वारा की जांच करने पर धमकी झूठी निकली।

सीएम रेखा गुप्ता की सख्ती के बाद निगम की बड़ी कार्रवाई, शहर से हटाई 16 हजार अवैध होर्डिंग्स

नई दिल्ली। शहर को गंदा करने के साथ निगम के राजस्व को चूना लगा रहे अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती के बाद निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले दो माह में एमसीडी ने 16 हजार से अधिक होर्डिंग्स हटाने के साथ एक लाख से अधिक पोस्टर हटाए हैं। पहले यह कार्रवाई दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता के दौरान होती थी। निगम ने कार्रवाई के साथ यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्रीय उपायुक्त अपने-अपने इलाके का प्रतिदिन जमीनी निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि शहर को गंदा करने के साथ निगम की अधिकृत विज्ञापन साइट का उपयोग न करके दीवारों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स और पोस्टर न हो। निगम के अनुसार 1,00,370 पोस्टर मई और जून में हटाए हैं। इसी तरह उपरोक्त समय-सीमा में 39,075 बैनर और 16,642 होर्डिंग्स हटाए हैं। बता दें कि एमसीडी 14 हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में निगम का नेतृत्व चाहता है कि राजस्व के स्रोत को मजबूत किया जाए लेकिन विज्ञापन और पर्यावरण

प्रबंधन सेवाएं विभाग (डेम्स) की लापरवाही के चलते निगम को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा था। यही वजह है कि दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स पोस्टर आसानी से दिख जाते हैं लेकिन दिल्ली में सरकार के परिवर्तन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने सख्ती की तो निगम शहर को गंदा करने वालों पर कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। अधिकृत साइटों पर भी ही आउटडोर विज्ञापन होने चाहिए, लेकिन दिल्ली के रिहायशी इलाकों से लेकर व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग्स, वाल रैप की भरमार है। अवैध होर्डिंग्स पोस्टर आसानी से लग जाने से भी अधिकृत साइट पर विज्ञापन उतने नहीं आते । इससे निगम को राजस्व नुकसान होता है जिसकी मात्रा करोड़ों रुपये हो सकती है। नगर निगम की मेट्रो की संपत्ति पर लगाए गए विज्ञापनों से होने वाले राजस्व में 35 प्रतिशत की भागीदारी है। निगम को मेट्रो से आउटडोर एडवरटाइजिंग से मात्र 7.15 करोड़ रुपये का राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में हुआ है। इस पर पीतमपुरा से पार्षद अमित नागपाल ने सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के पास प्राइम लोकेशन हैं और वहां पर विज्ञापन यादा आते हैं। ऐसे में मेट्रो से 35 प्रतिशत राजस्व में भागीदारी कम है। साथ ही जो राजस्व आ रहा है वह भी बहुत कम है। इसमें राजस्व बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए विज्ञापन विभाग को इस पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

शुक्लाजी की जगह दलित, ओबीसी को भेजा जा सकता था, कांग्रेस नेता उदित राज का बेतुका बयान

नई दिल्ली । एक्सिओम-4 मिशन को पूरा करके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौट रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने बेतुका बयान किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब एससी-एसटी और ओबीसी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब किसी दलित,ओबीसी को भी शुभांशु शुक्ला की जगह भेजा जा सकता था। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वे सुरक्षित लौटें। उन्होंने वहां जो ज्ञान अर्जित किया है, उसे यहां बिखेरें। लोग उससे लाभान्वित हों। यह मानवता के लिए लाभकारी है।

कौशलता विकास एक संकट मोचक बौद्धिक अस्त्र है-एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण

सृष्टि रचयिता ने मानव को प्राकृतिक रूप से बौद्धिक क्षमता का अभूतपूर्व खजाना दिया है बस! जरूरत है उसे पहचान कर निखारने की,जिसके बलपर सफलताओं की हदें पार की जा सकती है! मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि खास करके हर मानव में अपने अपने स्तरपर अलग-अलग कौशलता समाई हुई है, बस इसी पहचान कर उसका विकास करना है, जिसे हम कौशलता विकास दिवस के नाम से मनाते हैं।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 15 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशलता दिवस मना रहे हैं, इसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसे प्रथम बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था और हर साल नई थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण रखा गया है इसलिए, आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से कौशलता विकास पर चर्चा करेंगे। साथियों बात अगर हम विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की करें तो, सामाजिक-आर्थिक सुधार की दिशा में ठोस प्रयास है जो जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, निरंतर गरीबी, बढ़ती असमानता, तेजी से तकनीकी परिवर्तन, जनसांख्यिकीय संक्रमण और अन्य जैसी चुनौतियों से जुड़े हुए हैं।युवा महिलाओं और लड़कियों, विकलांग युवाओं, गरीब परिवारों के युवाओं, ग्रामीण समुदायों, स्वदेशी लोगों और अल्पसंख्यक समूहों के साथ-साथ हिंसक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम भुगतने वाले लोगों को कई कारकों के संयोजन के कारण बाहर रखा जाता है, इसके अलावा, संकट ने काम की दुनिया में पहले से ही कई बदलावों को तेज कर दिया है, जो उन कौशल और दक्षताओं के बारे में अनिश्चितता को परत जोड़ते हैं जिससे हम कौशलता से ऐसा दक्ष हो जाते है कि हम नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियां,जैसे कि यूनेस्को- यूएनईवीओसी, काम की दुनिया में पहुंच बाधाओं को कम करके इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए प्राप्त कौशल को मान्यता प्राप्त और प्रमाणित किया जाता है, और बाहर के लिए, कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। स्कूली युवा और जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (एनईईटी) में नहीं है 2030 एजेंडा के लिए कार्रवाई के इस दशक के दौरान, सकारात्मक परिवर्तन और नवाचार उत्पन्न करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं में युवाओं की पूर्ण भागीदारी महत्वपूर्ण है।हमारे माननीय पीएम के ड्रीम प्रोजेक्टस में से एक है। भारत ने इसके लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया है जो उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, अच्छे काम रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशलता प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर कौशलता विकास के महत्व पर जन जागरण बहुत ही जोर शोर से करता है साथियों बात अगर हम विश्व कौशलता दिवस 15 जुलाई 2025 के बारे में जानने की करें तो, थीम-2025 के लिए, विश्व युवा कौशल दिवस की थीम -एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण- है। महत्वयह दिन युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में प्रासंगिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है।आयोजनइस दिन, विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद आयोजित किए जाते हैं, जिनमें युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है।भागीदारी-शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक,प्रशिक्षण प्रदाता और अन्य सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि युवा आवश्यक कौशल प्राप्त करें। दिनांक 12 जुलाई 2025 को देर शाम माननीय उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कौशल का विकास के बारे में कहा भारतीय संविधान में 22 दृश्य चित्रणों में एक गुरुकुल की भी छवि है। हम हमेशा से ज्ञान के दान में विश्वास करते रहे हैं। कोचिंग सेंटरों को अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग कौशल केंद्रों में बदलने के लिए करना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी और मेरे सामने और बाहर मौजूद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे इस बीमारी की गंभीरता को समझें। उन्हें शिक्षा में विवेकशीलता बहाल करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें कौशल के लिए प्रबल प्रशिक्षण की सख्त आवश्यकता है। साथियों बात अगर हम युवा कौशलता के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की करें तो, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई)- वर्ष 1950 में परिकल्पित, का उद्देश्य भारत में मौजूदा दीर्घकालिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है। पीएम स्किल्स विकास योजना (पीएमकेवीवाई)- 2015 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त स्किल्स प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। पीएम स्किल्स विकास योजना-यह भारत के युवाओं को 400 से अधिक स्किल्स पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर रोजगार योग्य स्किल्स के साथ सशक्त बनाने के लिए 2021 की शुरुआत की गई है। पूर्व सीखने की मान्यता- इसे 2015 में व्यक्तियों द्वारा अर्जित पूर्व स्किल्स को पहचानने के लिए लॉन्च किया गया था।

यह पीएमकेवीवाई के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके तहत एक निश्चित स्किल्स वाले या पूर्व सीखने के अनुभव वाले व्यक्तिको राष्ट्रीय स्किल्स योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार ग्रेड के साथ आरपीएल के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना- इसके साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए अपनी राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर स्किल्स प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई।कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन (स्मार्ट)- यह एकल खिड़की आईटी अनुप्रयोग प्रदान करता है जो स्किल्स पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की मान्यता, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित है।आजीविका के लिए स्किल्स अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)- इसका ध्यान अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला-स्तरीय स्किल्स पारिस्थितिकी तंत्र पर है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के साथ सहयोग किया गया है।

औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए स्किल्स सुदृढ़ीकरण-स्ट्राइव योजना आईटीआई और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले स्किल्स प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना है। पीएम युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान)- वर्ष 2016 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है; समर्थन और उद्यमिता समर्थन नेटवर्क तक आसान पहुंच और समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना। यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स (वाईयूवीए) योजना, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। कौशलाचार्य पुरस्कार- स्किल्स प्रशिक्षकों द्वारा किए गए योगदान को पहचानने और अधिक प्रशिक्षकों को स्किल्स भारत मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। शिक्षुता और स्किल्स में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से अप्रैल 2019 में बाहर निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए है। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण 2020 में शुरू किया गया, यह कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए एक पोर्टल है जनजातीय समुदाय के लिए विशेष पहल। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स - आदिवासी आबादी को कला और संस्कृति, हस्तशिल्प, कपड़ा और आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में मदद कर रहा है जिससे जनजातीय आबादी के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो रहा है। इसी प्रकार वन धन योजना आदिवासी समाज को नए अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ रही है। साथियों बात अगर हम विश्व को चलता दिवस 15 जुलाई के इतिहास की करें तो,18 दिसंबर 2014 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने सर्वसम्मति से श्रीलंका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव अपनाया, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्व को उजागर करने के लिए श्रीलंका ने जी 77 (77 देशों का समूह) और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी।

चुनाव आयोग और मतदाता !

बिहार के चुनावों से पूर्व राज्य की मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह राजनैतिक माहौल गरमाया हुआ है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने यह भारी कवायद करने से पहले देश के विभिन्न राजनैतिक दलों से विचार- विमर्श नहीं किया। मगर इसका अर्थ यह भी है कि राजनैतिक दल चाहते हैं कि मतदाता सूचियों के सत्यापन में उनकी भी ठोस हुई भूमिका हो। यदि इस तथ्य का हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि राजनैतिक दल चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहते है। भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतन्त्र व निष्पक्ष संस्था होती है जो सरकार का अंग नहीं है। चुनाव आयोग व न्यायपालिका को सरकार का अंग न बनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि भारत का लोकतन्त्र पूरी तरह निष्पक्ष व निष्कलंक रहे। चुनाव आयोग सीधे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है और यह भारतीय लोकतन्त्र की उर्वरा जमीन तैयार करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतन्त्र के मालिकाना हक केवल आम लोगों के हाथ में रहें। चुनाव आयोग यही काम करता है क्योंकि वह पांच साल बाद विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव करवाकर भारत की राजनैतिक आधार पर प्रशासन प्रणाली इस तरह तैयार करता है कि जो भी राजनैतिक दल या दलों का समूह विधानसभा व लोकसभा में बहुमत प्राप्त करे वही देश का शासन चलाये। भारत में यह कार्य चुनावों के माध्यम से ही होता है जिन्हें चुनाव आयोग सम्पन्न कराता है। इसका सबसे प्राथमिक व जरूरी काम मतदाता सूचियां तैयार करने का होता है। इसलिए यदि इसी में गड़बड़ी होगी तो ऊपर तक सारे लोकतन्त्र में अशुद्धि घुल जायेगी। चुनाव आयोग यदि किसी प्रकार की अशुद्धि को दूर करने के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रहा है तो इसमें राजनैतिक दलों को ऐतराज क्यों होना चाहिए? मगर सवाल यह है कि पुनरीक्षण का पैमाना क्या है। बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जो फार्मूला दिया है उसके अनुसार 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम थे उन्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है मगर इसके बाद से जो नये मतदाता जुड़े हैं उनकी विश्वसनीयता की वह जांच करेगा। इस बीच 18 साल से ऊपर होने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ से भी ऊपर मानी जा रही है। इन मतदाताओं के सत्यापन के लिए जो निर्देशावली चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई उसमें वोटर कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि बिहार में पिछले बीस सालों में जो चुनाव हुए हैं उनमें कुछ सन्देहस्पद मतदाताओं ने भी वोट डाले। ऐसे सन्देहस्पद मतदाताओं की छंटनी करने का ही इरादा आयोग का लगता है। मगर इस मामले के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुझाव दिया कि इन तीनों कार्डों को भी मतदाता सत्यापन का आधार बनाया जाये। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ऊपर मानी जाती है जिसमें से 97 प्रतिशत लोगों के पास आधार कार्ड है। बल्कि बिहार के सीमांचल कहे जाने वाले इलाके के चार जिलों में तो हालत यह रही है कि आधार कार्ड कुल आबादी से भी अधिक की संख्या में है। इसका मतलब यह है कि कुछ फर्जी आधार कार्ड भी हैं। हालांकि राशन कार्ड के बारे में यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह परिवार के आधार पर बनता है। मगर इसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है। राशन कार्ड बनाने का काम राज्य सरकारें करती हैं जबकि वोटर कार्ड खुद चुनाव आयोग तैयार करता है। अतः 2003 के बाद बिहार में जो भी वोटर कार्ड बने उनमें कुछ संदिग्ध है। चुनाव आयोग अब यह स्वीकार कर रहा है कि बिहार में कुछ नेपाली, बंगलादेशी व म्यांमारी लोगों के नाम भी मतदाता सूचियों में हैं। यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि संविधान के अनुसार केवल भारत के वैध नागरिक को ही सरकार ने मत देने का अधिकार दिया हुआ है। वोट का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भारत में लोकतन्त्र को जनोन्मुखी बनाने का लक्ष्य है। जिसका वादा स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से किया था और समानता के आधार पर भारत के हर जाति, धर्म के वयस्क स्त्री-पुरुष को वोट का अधिकार दिया था। स्वतन्त्रता के बाद इस समानता के वोट अधिकार को सरकार की नीति बनाया गया। इसी नीति पर हमारा लोकतन्त्र टिका हुआ है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वह पूरे देश में बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करेगा। इस बाबत उसने विभिन्न राज्यों के चुनाव आयुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं। इस पर भारत के विपक्षी दल भारी विरोध की मुद्रा में हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है जबकि पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। विपक्षी दलों का तर्क है कि बिहार के पुनरीक्षण मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है और संभव है कि सुनवाई और आगे तक भी हो अतः न्यायालय का फैसला आने का चुनाव आयोग को इन्तजार करना चाहिए था। मगर वह तो उल्टे पूरे देश में ही यह कवायद कराने की सोच रहा है। अगले वर्ष 2026 में असम, प. बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची नये सिरे से तैयार करने के लिए चुनाव आयोग ने 1जनवरी 2026 तारीख नियत की है। अर्थात इस तारीख से देश के सभी राज्यों (बिहार को छोड़कर) में चुनाव आयोग मतदाताओं के सत्यापन का काम शुरू कर देगा। विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह काम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही किया जाना चाहिए। गौर से देखा जाये तो चुनाव आयोग यह सुझाव स्वीकार कर सकता है और विभिन्न राजनैतिक दलों से इस बीच मन्त्रणा भी कर सकता है।

देश और समाज के लिए तन, मन, धन समर्पित करने की मिसाल हैं सी. सदानंदन मास्टर

पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में विशेष लोक अभियोजक रहे उज्ज्वल निकम, केरल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सी सदानंदन मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन चार नामों में से आपके लिए सी. सदानंदन मास्टर का नाम भले जाना-पहचाना नहीं हो लेकिन उनके सामाजिक कार्य उनकी पहचान हैं। साथ ही उनका जीवन अन्याय के आगे नहीं झुकने की भावना का प्रतीक भी है। वामपंथी हिंसा और धमकी के आगे नहीं झुक कर राष्ट्र के विकास के प्रति अपने जज्बे को बरकरार रखने वाले सी. सदानंदन मास्टर पूरे देश के लिए बड़ी प्रेरणा हैं। हम आपको बता दें कि केरल के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में जिन व्यक्तियों ने जनता के बीच संगठन, चेतना और संघर्ष की लौ जगाई, उनमें सी. सदानंदन मास्टर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक शिक्षक नहीं हैं, बल्कि जीवनपर्यंत एक ऐसे संगठक, विचारक और मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के माध्यम से केरल में राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती दी। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और आदर्शों के लिए समर्पित था, और आज भी वे केरल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सी. सदानंदन मास्टर का जन्म केरल के कन्नूर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत संयमी, मेहनती और अनुशासनप्रिय थे। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही गहरी थी। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बहुत जल्द गांव-समाज में एक आदर्श गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सदानंदन मास्टर का जीवन तब मोड़ लेता है, जब वे युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आते हैं। संघ के एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता के विचार ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। शिक्षक के दायित्व के साथ-साथ वे धीरे-धीरे संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय हो गए। उनका घर और स्कूल ही संघ की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। वे विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। हम आपको बता दें कि केरल के कन्नूर और आसपास के क्षेत्र वामपंथी राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे हैं। 1994 में सी. सदानंदन मास्टर पर एक क्रूर और अमानवीय हमला हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हिंसक कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट डाले थे। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा, शिक्षा और संगठन के प्रति समर्पण पर हमला था। लेकिन सदानंदन मास्टर ने इस हिंसा के आगे कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने उस घटना को अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे पैर काट दिए, लेकिन मेरे विचार और हौसले कोई नहीं काट सकता।

सम्पादकीय...

तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन

इस सदी के पहले दो दशकों के दौरान तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनियाभर में बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर से आज भारत के साथ-साथ समूचा विश्व ही दो-चार हो रहा है। इसकी वजह से उपजी आपदाओं के कारण न सिर्फ जान-माल की व्यापक क्षति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होने के लिए भी विवश होना पड़ रहा है। भारत में भी प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में भारत में 400 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है और इन आपदाओं का सबसे बड़ा नुकसान लोगों के घरों को हुआ है। साथ ही ये आपदाएं लोगों को अस्थायी और स्थायी रूप से विस्थापित कर रही हैं। जेनेवा स्थित इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी आईडीएमसी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में 1.18 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ये आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में 30 फीसदी अधिक है। साल 2022 में लगभग 32,000 और 2021 में 22,000 लोग बेघर हुए थे। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या भी चिंताजनक है, साल 2019 से 2023 के बीच भारत में कुल 281 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन केवल 2024 में ही 400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। वहीं, पिछले छह सालों में बाढ़ के कारण 55 फीसदी लोग आंतरिक रूप विस्थापन हुए, जबकि आंधी-तूफान के कारण 44 फीसदी लोग विस्थापित हुए। इसके अलावा भूस्खलन, भूकंप और सूखे जैसी अन्य जलवायु-संबंधी आपदाओं ने भी हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इसके इतर साल 2024 चिंताजनक था तो साल 2025 में हालात और भी बदतर हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, 2025 के छह महीनों में ही पूरे भारत में 1.6 लाख से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हुए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां 20 मई को मालदा के मथुरापुर में भी मिट्टी के कटाव के कारण लगभग 80,000 लोग विस्थापित हुए। जबकि राज्य में सिर्फ एक बड़ी बाढ़ की घटना दर्ज की गई थी। वहीं, असम दूसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां छह बाढ़ की घटनाओं में 42,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसी तरह त्रिपुरा में भी हालात गंभीर रहे, जहां 10 बाढ़ की घटनाओं में 21,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा। भारत अपनी विशिष्ट भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति पारंपरिक रूप से संवेदनशील रहा है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन यहां बार-बार होने वाली घटनाएं रही हैं। लगभग 60 फीसदी भूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंपों से ग्रस्त है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 8 फीसदी चक्रवातों से ग्रस्त है और 68 फीसदी क्षेत्र सूखे की चपेट में है। 1990-2000 के दशक में हर साल औसतन लगभग 4344 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 30 मिलियन लोग आपदाओं से प्रभावित हुए। निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान बहुत बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाया है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को एक रोडमैप में तब्दील किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सम्पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र में तैयारी, प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण तथा नवीन पद्धतियों, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयोग द्वारा न्यूनीकरण जैसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। पिछले दशक के दौरान भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के लगभग 2 दशक बाद, जिसमें 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, भारत ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को बदल दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के माध्यम से, इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना की। 2004 की सुनामी के कहर से बुरी तरह प्रभावित भारत ने वैज्ञानिक प्रगति, पूर्व चेतावनी प्रणाली और समुदाय-नेतृत्व वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए अपनी आपदा तैयारियों को काफी मजबूत किया है। यूएनडीआरआर द्वारा भारत को विश्व के उन पांच देशों में से एक माना गया है जो तटीय क्षेत्रों के लिए खतरे, वहां आने वाली लहरों की ऊंचाई का पूर्वानुमान लगा सकता है तथा भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूसी) के माध्यम से 'वास्तविक समय' में संवेदनशील इमारतों की पहचान कर सकता है, ताकि सम्पूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को पूर्व चेतावनी दी जा सके। इस समय भारत की पूर्व चेतावनी प्रणाली दुनिया की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणालियों में से एक है, जो न केवल देश के भीतर, बल्कि श्रीलंका, बंगलादेश, म्यांमार और थाईलैंड समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों को सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को 16 बटालियनों और 28 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्र विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए अच्छे तरह सुसज्जित और प्रशिक्षित है। वैश्विक स्तर पर भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पहचान (रिकग्निशन) और सुधार (रिफॉर्म) बहुत जरूरी है। 'पहचान' का मतलब ये समझना है कि आपदा को आशंका कहां है और वह भविष्य में कैसे घटित हो सकती है तथा सुधार का मतलब है कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें आपदा को आशंका कम हो जाए। इसके लिए हमें दो स्तर पर काम करना होगा। पहला, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को स्थानीय भागीदारी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और दूसरा, हमें आपदाओं से जुड़े खतरों से लोगों को जागरूक करना होगा। आपदा नियोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए पारंपरिक आवास और नगर नियोजन प्रक्रिया को भविष्य की प्रौद्योगिकी से समृद्ध किया जाना चाहिए।

75 की उम्र और रियाटरमेंट : संघ प्रमुख के बयान के मायने

अमरेंद्र कुमार राय

हुआ यूं कि मोहन भागवत ने आरएसएस के दिवंगत प्रचारक और वरिष्ठ नेता मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित एक पुस्तक मोरोपंत पिंगले - द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस के विमोचन के अवसर पर पिंगले से जुड़े कुछ किस्सों का जिक्र किया। पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले के बयान को उद्धृत करते हुए कहा वृंदावन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। वहां कार्यकर्ता आ रहे थे। उसी दौरान शेषाद्रि जी ने कहा कि आज अपने मोरोपंत पिंगले जी के 75 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर वे उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित करते हैं। फिर मोरोपंत पिंगले जी से बोलने का आग्रह किया। इस दौरान कार्यकर्ता मुस्करा रहे थे। मोरोपंत पिंगले खड़े हुए और कहा कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं। मैं समझ गया कि ऐसा इसलिए है कि शायद लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग पत्थर मारकर देखेंगे कि मैं मर गया हूं या नहीं। 75 साल की शाल जब ओढ़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि आपने बहुत किया और अब दूसरों को मौका दिया जाए। इसके आगे मोहन भागवत ने कहा कि मुझे मोरोपंत पिंगले जी का जिक्र करते हुए गर्व होता है। हम जो हासिल करते हैं या महिमा पाते हैं तो उससे चिपक जाते हैं। चिपकना नहीं चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद चर्चा यह चल पड़ी कि मोहन भागवत ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिये बिना इशारों ही इशारों में उन्हें 75 साल के बाद अपने पद से रिटायर हो जाने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1925 को अपने जीवन के 75 साल पूरे कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 17 सितंबर 1950 है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो 75 साल की उम्र की आड़ लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तब के दिग्गजों लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, सुमित्रा महाजन आदि को मार्ग दर्शक मंडल में भेज दिया था। अब चूंकि मोदी खुद 75 साल के हो रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि क्या मोदी खुद भी मार्ग दर्शक मंडल में जाएंगे ? इसी बीच मोहन भागवत का यह बयान आ गया है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 11 सितंबर 1925 है। यानी मोदी के 75 साल पूरे करने से एक सप्ताह पहले। अब मोदी समर्थक पूछ रहे हैं कि जो मोहन भागवत मोदी जी को और दिखाना चाहते हैं उसका पालन वे खुद भी इसी नियम के तहत रिटायर होंगे? अगर मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो भागवत क्यों नहीं ? जब कहा जा रहा है कि संघ में 75 साल पर रिटायर होने जैसी कोई नीति नहीं है तो मोदी समर्थकों का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी 75 की उम्र में रिटायर होने जैसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने जब यह फार्मूला बनाया तो वह दूसरों के लिए था। उनके लिए नहीं। लेकिन अब होगा क्या? क्या नरेंद्र मोदी भागवत के इशारे को समझते हुए प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या संघ उन्हें हटाएगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ इतना सामर्थ्यवान है कि वह मोदी को हटा सके? लोगों का कहना है कि संघ मातृ संस्था है। उसने बीजेपी को बनाया है। अभी तक बीजेपी में जो कुछ भी चलता आया है सब कुछ संघ की मर्जी से ही हुआ है। तो अभी भी संघ की मर्जी से ही होगा। संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे बड़े, पुराने और कद्दावर नेताओं को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया है। आडवाणी को तो जिन्ना की मजार पर जाने के लिए उन्हें साइडलाइन ही कर दिया। आडवाणी जैसा ताकतवर नेता कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यहां स्थितियों में फर्क है। न तब की बीजेपी है न नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। पहले बीजेपी को संघ की मदद की जरूरत थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि अब बीजेपी को संघ की मदद की जरूरत नहीं है। बीजेपी खुद में बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। यह बात सच भी है। अब की बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 14 करोड़ को पार कर चुकी है। यह करिश्मा नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के कारण ही संभव हो सका है। इसके विपरीत संघ के सदस्यों की संख्या अभी भी 50-60 लाख के बीच बताई जाती है। आप खुद सोचिये कि 50-60 लाख सदस्यों वाला संघ अपने से 25 गुना से भी ज्यादा बड़े संगठन पर कितना दबाव बना पाएगा? फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी वाजपेयी और आडवाणी से कहीं बहुत ज्यादा है। इन दोनों के नेतृत्व में पार्टी बहुत मुश्किल से सत्ता तक पहुंच पाई थी। वह भी सहयोगी पार्टियों के समर्थन से। जबकि नरेंद्र मोदी ने दो बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को कॉरपोरेट जगत का पूरा समर्थन है, जिसके चलते मीडिया पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है। इसके साथ ही तमाम संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग यहां तक कि अदालतों पर भी मोदी जी का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। फिर जन समर्थन भी मोदी के पास है। ऐसे में संघ किस आधार पर मोदी पर दबाव बना पाएगा। यह तो हो सकता है कि अगर मोदी बात न मानें तो संघ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनकी सरकार गिरा दे। क्योंकि जीते हुए बहुत से सांसद अभी भी संघ के प्रभाव में हैं और उन्हें अगर संघ और बीजेपी में चुनना हो तो वे संघ को प्राथमिकता देंगे। लेकिन क्या संघ ये चाहेगा कि मोदी की सरकार गिर जाए? यह स्थिति तो उसके लिए और भी घातक होगी। अभी तो मोदी भले अपनी मनमर्जी चला रहे हैं पर संघ के भी तो कुछ काम हो ही रहे हैं। दूसरे अगर मोदी ने कहीं जवाबी हमला किया तो हो सकता है कि संघ समर्थक सांसद भी अपनी जान बचाने के लिए मोदी की शरण में जाने को मजबूर हो जाएं। जैसे मायावती, चंद्रबाबू नायडू और दूसरे विपक्षी नेता खामोश हैं।

संघ का साथ देने पर मोदी भी खामोश क्यों बैठेंगे। ऐसे में अगर सीबीआई और ईडी संघ समर्थक सांसदों के यहां पहुंचने लगे तो कितने लोग संघ का साथ देंगे। खुद भागवत के यहां भी तो ईडी, सीबीआई जा सकती है। और जैसे संघ मोदी को हटाने के लिए बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर सकता है वैसे ही मोदी भी भागवत को हटाने के लिए संघ को भी बांट सकते हैं। संघ में कुछ मोदी के भी जबरदस्त पैरोकार हैं। यही वजह है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कभी कुछ नहीं कहते। वे इशारों-इशारों में ही पिछले एक साल से अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि स्थिति की गंभीरता को वो भी समझते हैं। तो मोदी इतनी आसानी से सिंहासन नहीं खाली करने वाले।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पश्चिमी एन्क्लेव, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/06862)

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के अगले हिस्से में पोषण लेबल हो अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का नियामक को निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को पैक्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबल लागू करने का निर्देश दिया है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, जो संसद की अधीनस्थ विधायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। एफएसएसएआई एक स्वायत्त निकाय है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ सुरक्षित और स्वस्थ हैं। फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबल, खाद्य पदार्थों के पैकेज के सामने की तरफ दी गई जानकारी है, जो उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद करती है कि कोई उत्पाद कितना स्वस्थ है। यह जानकारी अक्सर एक सरल, संक्षिप्त और ग्राफिक प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है, जैसे कि रंग-कोडित प्रणाली या प्रतीक। देवड़ा ने लिखा कि मैंने सिंगापुर की स्पष्ट ए-टू-डी न्यूट्री-ग्रेड प्रणाली का अध्ययन करने की सिफारिश की है। देवड़ा की पोस्ट के अनुसार इस कदम से एफएसएसएआई को बिना किसी देरी के अनुपालन करने और भारतीय उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इससे देश में बढ़ते मोटापे के संकट को रोका जा सकेगा। ए-टू-डी न्यूट्री-ग्रेड प्रणाली खाद्य पदार्थों में, एक ग्रेडिंग प्रणाली है जो खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्य के आधार पर वर्गीकृत करती है। यह प्रणाली खाद्य पदार्थों को (सबसे अच्छा) से डी (सबसे खराब) तक के ग्रेड में विभाजित करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न स्थानों पर स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए चीनी और तेल बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, ये बोर्ड स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक संस्थानों में दृश्यात्मक व्यवहारिक संकेतों के रूप में काम करेंगे। इन पर रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में छिपे वसा और शक्कर की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। सोमवार को देवड़ा ने कहा कि भारत को बढ़ते मोटापे की समस्या से निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के साथ-साथ जलेबी और समोसे जैसे भारतीय स्नैक्स पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम कार्यस्थलों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख पहल का हिस्सा है। इनमें तेल और चीनी के अत्यधिक सेवन को कम करना शामिल है, जो मोटापा, मधुमेह, उच रक्तचाप और अन्य जीवनशैली संबंधी विकारों की बढ़ती दरों में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

इस साल शेयर बाजार में ये पांच स्टॉक्स मचा सकते हैं जबरदस्त धमाल, मिलेगा उम्मीद से भी बढ़कर रिटर्न

बिजनेस डेस्क।

शेयर बाजार में कौन से शेयर शानदार रिटर्न देंगे इस पर लगातार निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहती है. उसी हिसाब से वे स्टॉक मार्केट में अपना दांव लगाते हैं. लेकिन, ये जरूर है कि जब भी आप पैसे लगाएं तो जरूर एक बार बाजार विशेषज्ञों की सलाह पर भी गौर करें. आइये आज हम आपको उन पांच स्टॉक्स के बारे में बता जा रहे जिसके बारे में बाजार के जानकार ये मानते हैं कि इस साल यानी 2025 में ये आपको 26 प्रतिशत तक जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं. इसके लिए ईटी नाऊ समेत अन्य ब्रोकरेज फर्म्स की सलाह के हिसाब से यहां पर बताया जा रहा है कि आखिर उनका क्या कुछ मानना है.

1-हुंडई मोटर्स इंडिया

हुंडई मोटर्स का मौजूदा शेयर वैल्यू 2103 रुपये के आसपास है और इसे हाल में ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2600 रुपये तक बताया है. इस साल इसके शेयर करीब 23 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ने की उम्मीद की जा रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हिकल सेगमेंट को लेकर कंपनी की रणनीति, इंडियन मार्केट में इसकी तेजी से मांग और नई लॉन्चिंग की वजह से इसके स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

2-सुप्रजीत इंजीनियरिंग

सुप्रजीत इंजीनियरिंग को लेकर के अनुमान लगाया गया है कि इसके शेयर इस साल करीब 22 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ सकते हैं. ब्रोकरेज फर्म एमके ने निवेशकों को इसमें पैसा लगाने की सलाह देते हुए कहा कि भले ही इस शेयर का भाव अभी 448 रुपये के करीब है लेकिन इस साल ये 550 रुपये तक छलांग लगा सकता है.

3-लक्ष्मी डेंटल

लक्ष्मी डेंटल के स्टॉक का वर्तमान में भाव 427 रुपये का चल रहा है और इसका इस साल का टारगेट प्राइस 26 प्रतिशत ग्रोथ के साथ 540 रुपये का रखा गया है. उपकरण निर्माण और डेंटल हेल्थ में तेजी के साथ आगे बढ़ रही लक्ष्मी डेंटल में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना बाजार के जानकार बता रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसके शेयर पर बाय की रेटिंग देते हुए कहा कि इसमें लंबे समय में निवेशकों के लिए जबरदस्त संभावना हो सकती है.

4-टीसीएस

टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक भाव वर्तमान में 3265 रुपये का चल रहा है. लेकिन ब्रोकरेज फर्म चॉइस ने 3950 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हुए इसके बाय की सलाह दी है. फर्म का कहना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर में स्टैबिलिटी और क्लाइंट रिटेंशन के दम पर ये स्टॉक तेजी के साथ इस सार उछल कर निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकते हैं.

5-हिन्दुस्तान यूनिलीवर

एफएमसीजी सेक्टर की जानी मानी की कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर की गांव से लेकर शहर तक के बाजार में खास पकड़ है और ये इसी वजह से इन्वेस्टर्स की पसंद बनी हुई है. इसके शेयर का मौजूदा रेट 2520 रुपये चल रहा है.

लेकिन ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसकी बाय रेटिंग देते हुए इन्वेस्टर्स से इस पर रिटर्न की उम्मीद जताई है. इसका टारगेट प्राइस 3000 रुपये तक किया है, जो करीब 19 प्रतिशत तक की उछल को दर्शाता है. इन पांचों स्टॉक्स में 2025 के दौरान अच्छे रिटर्न की संभावना है. फिर भी, निवेश से पहले आपकी जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और बाजार की परिस्थितियां जरूर ध्यान में रखें.

एनवीडिया को चीन में एच20 एआई कंप्यूटर चिप्स बेचने के लिए अमेरिका की मंजूरी मिली, सीईओ का दावा

नई दिल्ली ।प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया को चीन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने में इस्तेमाल होने वाले अपने उन्नत एच20 कंप्यूटर चिप्स बेचने के लिए ट्रम्प प्रशासन से मंजूरी मिल गई है। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने यह दावा किया है। यह खबर सोमवार देर रात कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में आई और हुआंग ने एक्स पर पर भी इसका जिक्र किया। हुआंग ने चीन के सरकारी सीजीटीएन टेलीविजन नेटवर्क पर भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि, दुनिया के सबसे अधिक एआई शोधकर्ता चीन में हैं। उन्होंने कहा कि चीन में यह इतना नवीन और गतिशील है कि यह वास्तव में जरूरी है कि अमेरिकी कंपनियां चीन में प्रतिस्पर्धा करने और बाजार की सेवा करने में सक्षम हों। हुआंग ने हाल ही में ट्रम्प और अन्य अमेरिकी नीति निर्माताओं से मुलाकात की थी और इस सप्ताह वे आपूर्ति शृंखला सम्मेलन में भाग लेने और चीनी अधिकारियों से बात करने के लिए बीजिंग में हैं। प्रसारण के दौरान हुआंग को चाइना कार्यसिल

फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के प्रमुख रेन होंगबिन से मिलते हुए दिखाया गया, जो चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो के मेज़बान हैं, जिसमें हुआंग भी शामिल थे।

इस कार्यक्रम में एनवीडिया एक प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हुआ। एनवीडिया को एआई को तेजी से अपनाने से भारी मुनाफ़ा हुआ है। पिछले हफ्ते यह 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता इस उद्योग पर भारी पड़ रही है। वाशिंगटन वर्षों से चीन को उन्नत तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा करता रहा है, इस चिंता का हवाला देते हुए कि नागरिक उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जनवरी में चीन के डीपसीक एआई चैटबॉट के उभरने से इस बात पर चिंताएँ फिर से बढ़ गईं कि चीन अपनी एआई क्षमताओं को विकसित करने में मदद के लिए उन्नत चिप्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जनवरी में, ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले, राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्नत कंप्यूटर चिप्स के निर्यात के लिए एक नया ढांचा शुरू किया, जो उत्पादकों और अन्य देशों के आर्थिक हितों के साथ प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने का एक प्रयास था। व्हाइट हाउस ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह चीन को एनवीडिया के एच20 चिप्स और एएमडी के एमआई308 चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। एनवीडिया ने कहा था कि कड़े निर्यात नियंत्रणों से कंपनी को 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त नुकसान होगा, और हुआंग और अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की सीमाएं दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी बाजारों में से एक, एक अग्रणी क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा की राह में बाधा डालती हैं।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के कारण अन्य देश चीन की एआई प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ सकते हैं।

क्रैश हुआ टाटा ग्रुप का यह शेयर, घबराहट के कारण निवेशकों में बेचने की होड़

बिजनेस डेस्क। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में आज भारी गिरावट देखी गई. आज कंपनी के शेयर 10 परसेंट से यादा टूटकर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गए. शेयरों में इस गिरावट की बड़ी वजह कंपनी को जून तिमाही में हुआ नुकसान है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी को 194 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जिसका असर इसके शेयरों पर देखने को मिल रहा है. NSE पर तेजस नेटवर्क का शेयर 7.50 परसेंट से यादा टूटकर 645 रुपये पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 698.40 रुपये था. कारोबार के दौरान यह 10.16 परसेंट की गिरावट के साथ 627.45 रुपये के इंट्राडे-लो लेवल को टच किया, जो 52-हफ्तों का निचला स्तर है. दोपहर 12:30 बजे तेजस नेटवर्क्स के शेयर 5.50 परसेंट की गिरावट के साथ 661 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे. लगभग तभी टाटा की इस कंपनी के 53 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ. शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं. तेजस नेटवर्क्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड की है. इसके शेयरों में आज बिकवाली पहली तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के चलते हुआ. वित्त वर्ष 2026 की जून तिमाही में तेजस नेटवर्क्स ने बिक्री में आई गिरावट के चलते कंपनी को 193.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. जबकि इस कंपनी ने एक साल पहले इसी तिमाही BSNL को 4जी उपकरणों की सप्लाई कर 77.48 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था. तेजस नेटवर्क्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जून 2024 तिमाही के 1,563 करोड़ रुपये से लगभग 87 परसेंट घटकर 202 करोड़ रुपये रह गया. इस पर सफाई देते हुए टाटा ने कहा, कंपनी को इस तिमाही में भारतनेट फेज-3 के लिए राउटर और और भारत में निजी ऑपरेटरों से ऑप्टिकल उपकरणों के ऑर्डर मिले. कंपनी ने कहा कि रेवेन्यू में आई यह कमी BSNL सहित अन्य कंपनियों से ऑर्डर मिलने में देरी के चलते हुई. तिमाही के अंत तक तेजस नेटवर्क्स का ऑर्डर बुक 1,241 करोड़ रुपये का रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 22 परसेंट यादा है.

व्यापार युद्ध के दबाव में भी नहीं झुका चीन, बढ़ती जीडीपी दर ने चौंकाया

बीजिंग । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था ने अप्रत्याशित मजबूती दिखाई है। अप्रैल से जून की तिमाही में चीन की जीडीपी दर 5.2 प्रतिशत रही है, जो वैश्विक विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर है। जनवरी-मार्च में यह दर 5.4 प्रतिशत थी। सरकार के मुताबिक तिमाही आधार पर 1.1 प्रतिशत की बढ़त भी दर्ज हुई है, जो एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में घरेलू निवेश और वैश्विक निर्यात ने बड़ा योगदान दिया है। फैक्ट्रियों, हाई-स्पीड रेलवे और बुनियादी ढांचे में निवेश को तेज किया गया। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन ने अपने उत्पादों को दक्षिण-पूर्वी एशिया जैसे देशों के ज़रिए निर्यात करना शुरू किया, जहां से वे अमेरिका और यूरोप को पुनः निर्यात हुए। इससे अमेरिका में गिरते निर्यात की भरपाई हो सकी।

खर्च प्रोत्साहन कार्यक्रम का कमाल

चीन की सरकार ने बीते साल से एक बड़ा खर्च प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया। इसमें लोगों को इलेक्ट्रिक कार, एयर कंडीशनर और अन्य सामान खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई। इससे फैक्ट्रियों को राहत मिली, जो कीमत युद्ध और जरूरत से यादा क्षमता की वजह से घाटे में चल रही थीं। हालांकि कुछ शहरों में यह योजना इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि सरकारी कोष पर भी दबाव बढ़ने लगा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन सब के बावजूद जीडीपी बढ़ाने में ये योजना काफी काम की रही।

अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन

चीन के बारे में अमेरिकी मिडिया कहता है कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन पहले की अपेक्षा बेहतर रहा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने तो अपने

पूरे साल के अनुमान को 4.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया है। यह तब हुआ है जब अमेरिका के टैरिफ कुछ समय के लिए 145 प्रतिशत तक पहुंच गए थे, जिससे चीन के निर्माण क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा था कि ड्रैगन की डगमगा सकती है, लेकिन डगमगाना तो दूर चीन ने इस बार उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन किया।

मुनाफा कम हुआ तो सरकार ने ऐसे की मदद

एक ओर जहां मांग को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर कीमतों में गिरावट की वजह से कंपनियों का मुनाफा घट रहा है। अपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक कार और अन्य बड़े उत्पाद अब सस्ते हो रहे हैं। इसे डिफ्लेशन कहते हैं, जो कंपनियों के मुनाफे और वेतन दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। लोगों की आमदनी घटने से खर्च और कर्ज चुकाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। डिफ्लेशन की चुनौती से निपटने के लिए चीन ने ब्याज दरों में भारी कटौती की है। सरकारी बॉन्ड की दरें 11 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं। इससे रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र को सस्ते ऋण मिल रहे हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला है। लेकिन फिर भी हाउसिंग सेक्टर में स्थिरता नहीं आ सकी है और कीमतें फिर से गिरने लगी हैं।

खर्च बढ़ाने के लिए सरकार ने लिए ये फैसले

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को लोगों के हाथ में और पैसा देना चाहिए ताकि वे यादा सामान खरीद सकें। लेकिन प्रांतीय सरकारों के पास सीमित संसाधन हैं। सरकार ने पेंशन में भी इस बार औसतन केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो पहले से ही बहुत कम है। हालांकि कई विश्लेषक चीन के सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बीजिंग के लिए जीडीपी लक्ष्य हासिल करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस साल चीन ने 5 प्रतिशत ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, और फिलहाल के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि वह इसे हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।

जिनपिंग के आंकड़ों पर उठे सवाल

चीन के कैपिटल इकोनॉमिक्स के विश्लेषण में कहा गया है कि वास्तविक वृद्धि इससे कहीं कम, करीब 3.5फीसदी हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल और मई में जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 4फीसदी से भी नीचे रही। फैक्टरी और मशीनरी में निवेश भी धीमा पड़ा है

। केवल जून में ही इस क्षेत्र में 0.5फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई। घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। उपभोक्ता कीमतों में 0.1फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे डिमांड घटने के संकेत मिलते हैं। चीन की सरकार ने 2025 के लिए 5फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, लेकिन 12 अगस्त तक अगर अमेरिका-चीन के बीच नया ट्रेड समझौता नहीं हुआ, तो 245 फीसदी तक के टैरिफ दोबारा लागू हो सकते हैं। इससे निर्यात और रोजगार दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

हमारी बेटी को इंसाफ दो, वरना हम सब मर जाएंगे! परिवार के 9 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या करने की दी धमकी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहाँ एक ही परिवार के नौ लोगों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी दी है। यह परिवार अपनी बेटी की मौत के बाद कथित रूप से दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होने से परेशान है। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली लेकिन पुलिस कार्रवाई से बच रही थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। पुलिस मुख्यालय में परिवार समेत आत्महत्या करने की धमकी देने वाले बलवीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मार्च 2017 में की थी। उन्होंने कहा, उस समय हमने उसकी शादी पर 15 लाख रुपये खर्च किए थे और दूल्हे के परिवार को 2 लाख रुपये नकद, एक मोटरसाईकिल, सोने-चांदी के गहने दिए थे। हमने दूल्हे को उनके नए घर के लिए फर्नीचर, फ्रिज और एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए 1.75 लाख रुपये नकद भी दिए थे। हमने उस परिवार की मांग पर इतनी बड़ी रकम दी थी। बलवीर ने पुलिस कमिश्नर को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद ही महिला के ससुराल वालों ने उसे और दहेज की मांग करते हुए नियमित रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। बलवीर ने बताया, उन्होंने शादी के दौरान दिए गए सोने-चांदी के जेवर यह कहकर छीन लिए कि वे सुरक्षित रखने के लिए हैं। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरी कार मांगने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी बेटी ने कहा कि हम इतनी कार नहीं खरीद सकते तो उन्होंने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और शादी के लिए 5 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे। मृतक महिला के पिता के अनुसार अपने पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों सालों तक दुर्व्यवहार और अपमान सहने के बाद उनकी बेटी ने 5 अप्रैल को अपनी ससुराल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से ही परिवार लगातार पुलिस से संपर्क कर रहा था लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं की जा रही थी। इससे परेशान होकर सोमवार को पूरा परिवार दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुँचा और आत्महत्या की धमकी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब सभी प्रयास निष्फल हो गए तब उन्होंने यह कदम उठाया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, परिवार ने लिखित बयान दिया है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया में समय लग रहा था इसीलिए मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

20 दिन बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे शुभांशु

- स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई
- 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था

शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन रहा

शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा। शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4.45 बजे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ था।

कैलिफोर्निया। शुभांशु शुक्ला सहित चार एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 बजे आईएसएस पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी।

पीएम मोदी बोले- यह गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर

पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौट आने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें पीएम मोदी ने लिखा मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।

मानसून सत्र से पहले धनखड़ से मिले खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- सार्थक सत्र चाहता है विपक्ष

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष एक सार्थक सत्र चाहता है। संसद का एक महीने तक चलने वाला मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का एक सार्थक सत्र चाहता है। इसके लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा की आवश्यकता है, जो जनता के लिए बहुत चिंता का विषय हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने धनखड़ के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आज मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति से मुलाकात की और एक उपयोगी बातचीत हुई। खड़गे ने कहा, विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का सफल सत्र चाहता है। ऐसा होने के लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की आवश्यकता है, जो बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। उनका कहना था, आज मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति से मुलाकात की और सार्थक बातचीत हुई। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से आरंभ होकर 21 अगस्त तक चलेगा।

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, 16 जुलाई को होनी थी सजा

दोनों देशों के धर्मगुरुओं ने की बातचीत; हत्या के मामले में कल गोली मारी जानी थी

सना । यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजा-ए-मौत दी जानी थी। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद निमिषा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई है। इससे पहले निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर भी कई कोशिशें की गई थीं। खबर यह भी है कि पीड़ित का परिवार अभी तक क्षमादान या ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन से चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफिज बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं।

शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुसलियार और यमन से चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफिज इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। यमन शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ है। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जो पीड़ित परिवार को दोषी को बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले में माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। भारतीय नर्स निमिषा 2017 से जेल में बंद हैं, उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है।

ये सिस्टम की हत्या,जिन्हें रक्षा करनी थी, वही..., आत्मदाह के बाद छात्रा की मौत पर राहुल गांधी

नई दिल्ली ।

ओडिशा के बालासोर में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा के आत्मदाह करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रा की मौत को लेकर भाजपा पर हमला बोला है।

जबकि ओडिशा के राज्यपाल ने छात्रा की मौत पर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं ओडिशा के सीएम ने 20 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे-सीधे भाजपा के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय, उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार-बार अपमानित किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी, वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह भाजपा का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं। और आप खामोश बैठे हैं?

राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि

ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने भी छात्रा की मौत पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा ट्वीट में लिखा कि फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की एक छात्रा की असामयिक मृत्यु की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उसका निधन सिर्फ एक त्रासदी नहीं है। यह हमारे परिसरों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की एक स्पष्ट चेतावनी है। कानून अपना सबसे कठोर कदम उठाएगा। जिम्मेदार लोगों को कठोरतम सजा मिलेगी। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। असहनीय पीड़ा की इस घड़ी में उन्हें शक्ति मिले।

सरकार ने किया मुआवजे का एलान

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कॉलेज छात्रा के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, माझी ने संबंधित अधिकारियों को घटना की उचित जांच करने का निर्देश दिया ताकि सभी दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।

धर्मेंद्र प्रधान ने किया पलटवार

राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ओडिशा की बेटी के साथ हुई दुखद घटना पर ओछी राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका बना लिया है।

प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा हर दुर्घटना में अवसर तलाशने का काम किया है। इस घटना पर ओडिशा सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह समय सस्ती राजनीति का नहीं, बल्कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का है। राहुल गांधी को अपने इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के लिए पीड़ित परिवार से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी, लगातार दूसरे दिन आया धमकी भरा ईमेल

पंजाब। अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी फिर से मिली है। धमकी भरा ईमेल लगातार दूसरे भी आया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी के बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में विस्फोटक रखे होने की चेतावनी वाले इस ईमेल के बाद एसजीपीसी अधिकारियों और पंजाब पुलिस दोनों ने तुरंत और समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नान ने पुष्टि की कि धमकी भरे ईमेल में आरडीएक्स की मौजूदगी और पवित्र स्थल को संभावित नुकसान का जिक्र था।

65 दिनों में 22 बार ट्रंप ने लिया संघर्ष विराम का श्रेय, जयराम रमेश ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय कई बार लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने यह दावा 65 दिनों में 22 बार किया है। महासचिव ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलावर को इससे संबंधित पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के दावों का खुले तौर पर खंडन न करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना की है। रमेश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने सोमवार को नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान दोबारा यही दावा किया। ट्रंप ने कहा कि हम युद्धों को सुलझाने में बहुत सफल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात थे, उससे तो दोनों देश एक हफ्ते में ही परमाणु युद्ध में उलझ जाते। यह बहुत बुरी तरह से चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार को लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी रणनीति की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि हमने व्यापार के जरिए ऐसा किया। मैंने कहा था कि जब तक आप इस मामले को सुलझा नहीं लेते हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। 8 जुलाई को जब डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से बातचीत के दौरान यही दावा किया था, तो जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। रमेश ने कहा था कि पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सब ठीक उसी समय कहा जब वह भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे थे।

ओवैसी की पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी और साथ ही उन्हें नई याचिका दायर करने की भी अनुमति दी, जिसमें देश में राजनीतिक पार्टियों के मामले में संशोधन की मांग की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एआईएमआईएम का चुनाव आयोग में पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति नरसिम्हा मुरारी नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि एआईएमआईएम ने अपने उद्देश्य में बताया है कि यह पार्टी मुस्लिम समुदाय की सेवा करना चाहती है। ऐसे में इस पार्टी को जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29ए के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह देश के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन अदालत में पेश हुए।

ये कलम नहीं कट्टा वाले लोग हैं..., तेजस्वी यादव पर भड़के प्रशांत किशोर

पटना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के मीडिया को लेकर की गयी टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुये कहा कि यह उनके संस्कार और संस्कृति को दर्शाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सूत्र को लेकर जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है , वह किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से बेहतर शब्दों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह लोग कलम वाले नहीं कट्टा वाले लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव और उनके परिवार ने बिहार को एक समय कट्टा संस्कृति में ढकेल दिया था। जनसुराज नेता ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद के शासन में बिहार कट्टा बनाने और बेचने वाले प्रदेश के रूप में बदनाम हुआ था। यदि ऐसे लोग फिर से सत्ता में आ गए तो अपहरण, डकैती, लूट और जंगलराज वापस आ जाएगा। उन्होंने विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष पर भी तीखे प्रहार किये. उन्होंने कहा कि बिहार की कानून- व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त, दंगा-रोधी बंदूकें और आईईडी भी बरामद

मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने मंगलवार को पहाड़ी राज्य में 86 हथियार और 974 गोला-बारूद बरामद किए, जो पिछले कुछ वर्षों में घातक जातीय संघर्ष का गवाह रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने मणिपुर डीजीपी कार्यालय के हवाले से बताया कि संयुक्त अभियान में, बलों ने इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिले के इलाकों में ग्रेनेड, आईईडी, एके सीरीज और इंसास राइफलें, पिस्तौल, दंगा-रोधी बंदूकें और एसबीबीएल जब्त किए।

कुशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकतः सीएम योगी

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है और ''डबल इंजन सरकार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। बयान के अनुसार, योगी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जनपदों के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। योगी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा, कुशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। सीएम कहा, डबल इंजन (केंद्र और राज्य) सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। योगी ने प्रदेश के युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले आठ वर्षों में परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित किया है तथा दो करोड़ युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से 50 लाख युवा अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।

योगी ने उत्तर प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों में कानून-व्यवस्था में सुधार और सरकार की सकारात्मक नीति के कारण 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये निवेश लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और 'मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित किया गया है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी के तहत डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जबकि विश्वकर्मा योजना के तहत एक लाख से अधिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान की गई है। उन्होंने युवाओं से हताश न होने और निरंतर प्रयास करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हताशा और निराशा में जीवन नहीं है तथा सही प्रशिक्षण और मेहनत से आप सफलता की नयी कहानी लिख सकते हैं।

भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद मिली जमानत

लखनऊ । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी मामले में दर्ज केस की सुनवाई मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम ने राहुल को हिरासत में लिया। इसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के बाद 20-20 हजार की दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी गई। यह मुकदमा उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा चल रहा है। एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। बता दें कि यह मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प से जुड़ी थी। शिकायत के अनुसार कि राहुल ने बार-बार अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। लखनऊ की अदालत ने पहली नजर में माना था कि राहुल के बयान से भारतीय सेना और उससे जुड़े लोगों और उनके परिवारों का मनोबल कम हुआ है। इस मामले में अदालत ने राहुल को पेश होने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।